तापमान
अधिकतम 39.2 डिग्री
न्यूनतम 29.6 डिग्री

हरिभूमि
महासमुंद भूमि
रायपुर, गुरुवार 4 जून 2026

सरायपाली | बसना | पिथौरा | बागबाहरा | तुमगांव | खरियार रोड

12 सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त आवेदनों एवं ...

12 आधार पंजीयन एवं अपडेट शिविर का हुआ ...

खबर संक्षेप

मारपीट के मामले में जुर्म दर्ज

महासमुंद। तुमगांव के बाजार चौक के पास फ्रीडम चौक में एक व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में तुमगांव थाने में जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस को प्रार्थी अरविंद वार्ड नं 08 तुमगांव ने बताया कि 30 मई की रात करीबन 11 बजे बाजार चौक के पास फ्रीडम चौक में यशवंत बंजारे के साथ बातचीत कर रहा था। उसी समय रोशन बांधे ने गाली गलौज कर पत्थर से सिर में मारा और जान से मारने की धमकी देते हुए नाली में उसे डूबाकर मारपीट की। मामले की रिपोर्ट पर धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

रेत फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट

महासमुंद। ग्राम रामाडबरी में रेत फेंकने की बात पर हुए विवाद में दो पक्षों की बीच मारपीट हो गई। मामले की रिपोर्ट पर पटेवा थाने में अलग-अलग मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को प्रार्थी नरेंद्र सोनटके निवासी ग्राम रामाडबरी ने बताया कि 02 जून की शाम करीबन 05 बजे वह केरामुडा रोड स्थित अपने खेत से ट्रैक्टर ट्राली में ईंट लोडकर वापस अपने घर मेरी पत्नी हसीना सोनटके के साथ पैदल आ रहा था। इसी दौरान पीपरी चौक, बंजारे दुकान के सामने समारू सोनटके ने उसके ऊपर रेत फेंक दिया। जब उसने पूछा कि रेत को क्यो फेंक रहे हो, तब समारू सोनटके ने गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दिया। जब उसकी पत्नी हसीना सोनटके बीच बचाव करने आयी तो उसके साथ भी गाली गलौज कर मापीट करने लगा। आवाज सुनकर जब उसकी मां प्रेमीन सोनटके, भाई शंकर सोनटके आकर बीच बचाव करने लगे, तब आरोपी समारू सोनटके, किशन सोनटके और छीता सोनटके ने मिलकर मेरी पत्नी हसीना, मां प्रेमीन सोनटके, भाई शंकर सोनटके के साथ भी मारपीट की। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5) के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं समारू सोनटके निवासी ग्राम रामाडबरी ने पुलिस को बताया कि वह शाम करीबन 5 बजे अपने घर के सामने रेत चाल रहा था, उसी समय शंकर सोनटके मेरे ऊपर रेत को क्यों फेंक रहे हो बोलकर गाली गलौज करने लगा और जब गाली गलौज करने से मना किया तब नरेंद्र सोनटके ने हाथ मुक्का एवं अपने चप्पल से मारपीट किया है। वहीं बीच बचाव करने आई मेरी पत्नी सीताबाई को प्रेमीन सोनटके, संगीता, महेश्वरी एवं बेटे किशन सोनटके के साथ संगीता ने गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट किया। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 191(2), 296 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

19 केंद्रों में प्री डीएलएड प्रवेश के लिए 4849 का पंजीयन, परीक्षा आज

कलेक्टर ने पर्यवेक्षकों एवं केंद्राध्यक्षों की बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

जिले के 19 परीक्षा केंद्रों में आज 4849 पंजीकृत परीक्षार्थी प्री डीएलएड की परिक्षा में शामिल होंगे। जिसका आयोजन आज गुरुवार को जिला मुख्यालय में एक पाली में होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक निर्धारित इस परीक्षा में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने परीक्षार्थियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारू परीक्षा संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्रों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं केंद्राध्यक्षों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, नोडल अधिकारी सृष्टि चंद्राकर, पर्यवेक्षक एवं केंद्राध्यक्ष मौजूद थे। कलेक्टर लंगेह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जाए। प्रवेश द्वार पर व्यापम द्वारा जारी निर्देशानुसार कड़ाई से चेकिंग व्यवस्था हो तथा प्रतिबंधित सामग्री बिल्कुल न ले जाने दी जाए। परीक्षार्थियों के प्रवेश, बैठक व्यवस्था एवं प्रश्नपत्र वितरण में समय पालन का विशेष ध्यान रखा जाए। परीक्षा केंद्रों में पेयजल व प्राथमिक उपचार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें। नकल या अनुचित साधनों के किसी भी प्रयोग पर कड़ी निगरानी के लिए अभ्यर्थियों की फ्रिक्सिंग और वीडियोग्राफी की जाएगी तथा पुलिस पेट्रोलिंग दल भी तैनात रहेगा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना पर तत्काल कार्रवाई हो। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और संयम का पालन कर परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व प्रातः 9:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। तत्पश्चात परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा। सभी अभ्यर्थी समय का विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्रों में पहुंचना सुनिश्चित करें। जिससे फ्रिस्किंग (सुरक्षा जांच) एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

परीक्षा केंद्रों के पास लगे होंगे जैमर

व्यापम के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण और केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तीन सदस्यीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। जिले में 19 परीक्षा केंद्रों के लिए (प्रत्येक 12 अभ्यर्थी के लिए 1 वीक्षक) कुल 405 वीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। मोबाइल फोन, वाई-फाई और अन्य संचार उपकरण को ब्लॉक करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा प्रत्येक कक्ष के लिए जैमर उपकरण की व्यवस्था तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों में फ्रिक्सिंग एवं सुरक्षा संबंधी कार्य के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

शिविर : जनप्रतिनिधियों के जाते ही अफसर कर्मी भी हुए नदारद

समाधान की रस्म अदायगी, अतिथियों के जाते ही टेबल कुर्सियां हुई खाली

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

शहर के नयापारा क्षेत्र में एक दिन पहले लगे समाधान शिविर में दो घंटे के भीतर ही अफसर और कर्मचारियों के नदारद होने की बात सामने आई जिसके बाद बुधवार को शहर के लोहिया चौक में समाधान शिविर आयोजित हुआ। अतिथियों के आने तक शिविर शुरु नही हुआ था और अतिथियों के आने के बाद शिविर जारी नही रह पाया।

समाधान शिविर का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना था, लेकिन, कार्यक्रम का आयोजन कुप्रबंधन और लेटलतीफी की भेंट चढ़ गया। शिविर में पहुंचे नागरिक उस समय हताश हो गए, जब उन्हें अपनी समस्याओं को बताने के लिए ही घंटों का इंतजार करना पड़ा। अतिथियों के जाते ही शिविर तकरीबन समाप्त हो गया और कर्मचारी भी अपने टेबल से नदारद हो गए। पूरे शिविर के दौरान विपक्षी दल की नजर बनी रही और लगातार सोशल मीडिया में इस बाबत पोस्ट आते रहे कि केवल दिखावे के लिए शिविर का आयोजन हो रहा।

कर्मी देरी से पहुंचे और जल्दी रवाना हो गए

नियमतः शिविर की शुरुआत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे से होनी थी। जिसके लिए बड़ी संख्या में नागरिक तो समय पर पहुंच गए थे। परंतु, शिविर में कर्मचारी तब तक सक्रिय नही हुए जब तक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा एवं अन्य जनप्रतिनिधी नही पहुंचे। कतारों में खड़े बुजुर्ग, महिलाएं और जरूरतमंद लोग तेज गर्मी और अव्यवस्था के बीच अपनी बारी का इंतजार करते रहे।

औपचारिकता मात्र बना शिविर

मुख्य अतिथि और अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल से रवाना हुए, दोपहर 2 बजे तक शिविर को समाप्त कर दिया गया। अधिकांश विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपनी औपचारिकता पूरी करते हुए स्टॉल समेट कर चले गए। स्थिति यह रही कि स्टॉल खाली होने के बाद यहां पहुंचने वाले नागरिकों की बात तक सुनने वाला कोई नही था।

विधायक ने दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

समाधान शिविर के दौरान मुख्य अतिथि विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचंद राठी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पवन पटेल, स्थानीय पार्षदगण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित रहे। विधायक सिन्हा ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में वार्ड क्रमांक 01, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22 एवं वार्ड क्रमांक 23 तक के नागरिकों की मांग एवं समस्याओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर द्वारा भी स्टॉल का अवलोकन कर नागरिकों से समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई।

तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की मौत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

■ हादसा इतना भीषण था कि जयराम देवांगन ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया

बागबाहरा में बुधवार को ट्रक की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जयराम देवांगन (50 वर्ष) निवासी ग्राम सेवाती कोल्दा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयराम देवांगन अपने निजी कार्य से बागबाहरा आए हुए थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि जयराम देवांगन ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जयराम देवांगन गांव में मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनकी अचानक हुई मौत से गांव के लोग स्तब्ध हैं। पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

बाइक की टक्कर से महिला घायल

महासमुंद। पानी लाने गई एक महिला बाइक की टक्कर से घायल हो गई। मामले की रिपोर्ट पर सरायपाली थाने में जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि वार्ड क्रमांक सात जोगनीपाली निवासी चंद्रकांति बारिक घर के सामने निर्मल साहू के वाहन धुलाई सेंटर के नल से पानी लाने पैदल गई थी। इसी दौरान ग्राम अर्जुंडा की ओर से आ रही मोटर सायकल सुपर स्प्लेंडर क्रमांक सीजी 06 जीएफ 0471 के चालक द्वारा अपनी वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते आकर चंद्रकांति बारिक को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया है। घटना में महिला घायल हो गई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट पर आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध धारा 125(ए), 281 बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

आईपीएल मैच के दौरान लगी शर्त की रकम को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट

महासमुंद। आईपीएल मैच के दौरान लगी शर्त की रकम को लेकर तुमगांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अलग-अलग मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस को तुमगांव के वार्ड नं0 12 भाठापारा निवासी उज्ज्वल पुरैना ने बताया कि 02 जून की रात करीब 07 बजे उसने कमलेश अजगले को फोन कर आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान हार जीत में जीते हुए 1000 रुपए को मांगा। इसके बाद वह रविंदर पुरैना के साथ रात्रि करीबन 07.30 बजे कमलेश अजगले के घर वार्ड नं 02 इंदरा कॉलोनी भाठापारा तुमगांव गया जहां उधार का पैसा मांगने पर कमलेश अजगले उसके पिता स्व पिताजी भगतराम पुरैना के बारे में अपशब्द कहने लगा। जब उसने मना किया तब आरोपी कमलेश अजगले द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगा। इसी दौरान राजू अजगले, रेखा अजगले एवं परिवार के अन्य लोग लोहे का चाकू और चापड़ लेकर आए और उसके ऊपर वार करने की कोशिश करने लगे, तब वह वहां से भाग गया। लेकिन आरोपियों ने उसके भाई रविंदर पुरैना को पकड लिया और चाकू, चापड़ से वार करने लगे, जिस पर उसने अपने भाई द्वारिका पुरैना को फोन लगाया, तब उसके साथ सुरेश पुरैना एवं रोशन बांधे आये और रविन्दर पुरैना को बीच बचाव कर छुडाने लगे, तब सभी आरोपी मिलकर द्वारिका पुरैना, सुरेश पुरैना एवं रोशन बांधे के साथ चाकू एवं चापड़ से मारपीट करने लगे। घटना में रविंदर पुरैना, द्वारिका पुरैना, सुरेश पुरैना को चोटें आई, वहीं रोशन बांधे को हल्की चोट आई। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 118(1), 296, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

इधर दूसरे पक्ष के कमलेश अजगले निवासी वार्ड नं 02 इंदरा कालोनी भाठापारा तुमगांव ने बताया कि 02 जून की रात करीबन 07 बजे मुझे उज्जवल पुरैना के भाई रविंदर पुरैना ने फोन करके कहा कि तुम्हारा लडका राजू अजगले आईपीएल क्रिकेट मैच में हार जीत में मेरे भाई उज्जवल पुरैना से 1000 रुपए हारा है और उसे नहीं दे रहा है, तब उसने रविंदर पुरैना और उज्ज्वल पुरैना को फोन से बोला कि तुम्हारा पैसा आकर ले जाओ। तब दोनो मेरे घर के पास रात्रि करीबन 07.30 बजे आये और पैसे की बात को लेकर गाली गलौच करने लगे, तब उसके द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उज्जवल पुरैना हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा एवं रविन्दर पुरैना अपने पास रखे लोहे के तब्बल से वार करने लगा। तब उसके लड़के राजू अजगले, मेरी पत्नी रेखा अजगले, भाई जयदेव अजगले बीच बचाव करने लगे। उसी दौरान द्वारिका पुरैना एवं सुरेश पुरैना एवं अन्य लोग भी अपने साथ लाठी, डंडा एवं लोहे का हथियार लेकर आये और हम लोगों से मारपीट करने लगे, जिससे उन्हें चोट लगी। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 118(1), 296, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

तुमगांव रोड ओवरब्रिज निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी

ओवरब्रिज बना हादसों का केंद्र, जान खतरे में

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

शहर का तुमगांव रोड मुख्य ओवरब्रिज सुरक्षा के मानकों पर पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। करोड़ों रुपये की लागत से बना यह पुल अब आम नागरिकों के लिए खतरनाक बन गया है। निर्माण में बरती गई तकनीकी खामियों और सुरक्षा इंतज़ामों की कमी के कारण यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस ओवरब्रिज के निर्माण के समय ही यातायात सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है।

पुल पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए हैं। साथ ही, भारी वाहनों के मुड़ने के लिए पर्याप्त जगह और सही मोड़ (टर्न) न होने के कारण स्थिति हर समय जोखिम भरी रहती है। पुल की बनावट के कारण बड़े ट्रक, डंपर और बसें मोड़ पर आसानी से नहीं मुड़ पाते हैं। इन्हें मोड़ने के लिए बीच सड़क पर काफी जगह घेरनी पड़ती है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। विशेषकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में यहां कई किलोमीटर तक जाम लग जाता है। संकीर्ण मोड़ और गलत तरीके से वाहन मोड़ने के कारण पीछे से आ रहे दोपहिया और चार पहिया वाहन अक्सर बड़ी गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं।

संकेतों और रोशनी का अभाव

ओवरब्रिज के पूरे क्षेत्र में यातायात नियमों का पालन होता नहीं दिख रहा है। यहां न तो कोई चेतावनी बोर्ड (साइन बोर्ड) लगा है और न ही रात के समय दिशा बताने के लिए कोई रोशनी या रिफ्लेक्टर लगे हैं। स्पष्ट निर्देशों के अभाव में बाहर से आने वाले वाहन चालक अक्सर गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन चला देते हैं, जिससे आमने-सामने की टक्कर का खतरा बहुत बढ़ जाता है।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल

लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। जनता ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से ओवरब्रिज की तकनीकी जांच कराने, मोड़ों पर स्पीड ब्रेकर लगाने, चेतावनी बोर्ड लगवाने और भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो भविष्य में यहां किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

भंवरपुर चौकी क्षेत्र में नल-जल योजना की पाइप चोरी करने वाले 8 लोग गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

पुलिस ने नल-जल योजना के तहत लगाए गए कीमती लोहे के पाइप चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 50,000 रुपये कीमत के पाइप बरामद किए हैं। चौकी भंवरपुर क्षेत्र के ग्राम ललितपुर में नल-जल योजना के अंतर्गत पानी टंकी का निर्माण और पाइप फिटिंग का कार्य चल रहा था।

प्रार्थी सुनील अग्रवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 और 9 मई की दरम्यानी रात अज्ञात चोरों ने पानी टंकी में लगे 6 नग लोहे के पाइप और एक लोहे का गेट वॉल्व चोरी कर लिया है। चोरी गए सामान की कुल कीमत 90,000 रुपये थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस को गुप्त सूत्रों और सायबर सेल की मदद से सूचना मिली कि कुछ स्थानीय युवक घटना वाली रात पानी टंकी के पास देखे गए थे। पुलिस ने संदेह के आधार पर बमणीडीह निवासी टीकेलाल, किशोर कुमार, किशन, जयकुमार, राजू यादव और पीयूष दीवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पाइप चोरी कर उन्हें पत्थरों पर पटक कर तोड़ा और फिर सागरपाली निवासी गणपत मिर्धा और खगेश मिर्धा को कबाड़ के भाव में बेच दिया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सागरपाली से चोरी किए गए पाइप के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस मामले में चोरी करने वाले 6 युवक और कबाड़ के रूप में सामान खरीदने वाले 2 व्यक्तियों सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 305(ई) और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

देश का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनेगा रायपुर में, अंतिम चरण में टेंडर प्रक्रिया

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

छत्तीसगढ़ में जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग को नई पहचान देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुंबई, सूरत और कोलकाता के बाद यह देश का चौथा जेम एंड ज्वेलरी पार्क होगा। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की पहल पर राजधानी रायपुर के पंडरी क्षेत्र में लगभग 9.616 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क विकसित किया जाएगा।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पीपीपी एप्रेजल कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। 30 वर्ष की लीज अवधि (नवीनीकरण सहित कुल 90 वर्ष) और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह पार्क प्रदेश में निवेश, रोजगार और उद्योग विकास के नए अवसर सृजित करेगा। प्रस्तावित जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क को केवल सराफा कारोबार का केंद्र ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के पहले 'वेडिंग डेस्टिनेशन मॉल' के रूप में भी विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत लगभग 3.5 लाख वर्गफुट क्षेत्र विशेष रूप से जेम्स एवं ज्वेलरी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, आयातकों-निर्यातकों और वर्कशॉप उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित रहेगा। चतुर्थ तल पर सम्मेलन, व्यापार बैठक एवं प्रदर्शनी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यहां आधुनिक दुकानें, थोक कार्यालय, सुरक्षित वर्कशॉप, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी सुविधाओं के साथ केंद्रीयकृत सुरक्षा और अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना में बीआईएस एवं हॉलमार्किंग केंद्र, सामान्य सुविधा केंद्र, बैंकिंग सुविधा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संस्थान तथा स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

पीपीपी एप्रेजल कमेटी से मंजूरी, डेवलपर तय होने के बाद बनेगी ड्राइंग डिजाइन

'वेडिंग डेस्टिनेशन मॉल' का भी विकास

वहीं, शेष उपलब्ध एफएआर क्षेत्र में डेवलपर को वाणिज्यिक और मनोरंजन गतिविधियों के विकास की स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत परिधान, फूल-सज्जा, फोटोग्राफी, विवाह आयोजन और अन्य विवाह-संबंधित कारोबारों के लिए स्थान विकसित किए जाएंगे, जिससे यह परिसर एक समेकित 'वेडिंग डेस्टिनेशन मॉल' के रूप में उभर सकेगा।

रोजगार के नए अवसर मिलेंगे

इस परियोजना राज्य में व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ-साथ रायपुर को जेम्स एवं ज्वेलरी कारोबार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पार्क की स्थापना से रायपुर एवं आसपास के राज्यों के ग्राहकों को विश्वस्तरीय जेम्स एवं ज्वेलरी खरीदारी का अनुभव प्राप्त होगा। स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

टेंडर की प्रक्रिया जारी

सीएसआईडीसी द्वारा आरपीएफ 24 अप्रैल को जारी किया गया। बोलियाँ 15 मई तक प्राप्त की गईं। उसी दिन तकनीकी बोलियाँ विधिवत खोली गईं। वर्तमान में बोली मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त बोलियों का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया प्रगति पर है। जो बोलीदाता तकनीकी चरण में अर्ह पाये जाएंगे उन्हें वित्तीय बोली खोले जाने की तिथि से सूचित किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया में बोली का आधार जेम एंड ज्वेलरी पार्क के लिए अधिकतम लीज प्रीमियम होगा। शीघ्र ही सफल बोलीदाता का चयन कर परियोजना कार्यान्वयन के लिए करार किया जाएगा।

सराफा उद्योग के लिए ऐतिहासिक : राजीव अग्रवाल

सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि 2015 से यह परियोजना अटकी हुई थी। छत्तीसगढ़ के सराफा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। कौशल विकास, बीआईएस प्रमाणन एवं हॉलमार्किंग सुविधाओं के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि होगी। पीपीसी मोड पर विकास के कारण राज्य शासन पर न्यूनतम वित्तीय भार पड़ेगा।

खबर संक्षेप

तेलीबांधा तालाब के पास तेलीन दाई की मूर्ति लगाने की मांग

रायपुर। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नगर निगम स्थित कक्ष में सोमवार को रायपुर शहर जिला साहू संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर तेलीबांधा तालाब में माता तेलीन दाई की मूर्ति स्थापित करने की मांग की है। साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि रायपुर शहर का ऐतिहासिक तेलीबांधा तालाब साहू तेली समाज की प्राचीन धरोहर और सांस्कृतिक पहचान है। यह स्थान न केवल जनमानस के आकर्षण का केंद्र है, बल्कि समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी गहरा जुड़ाव रखता है। समाज की अस्मिता और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तेलीबांधा तालाब के समीप माता तेलीन दाई की एक भव्य मूर्ति स्थापित की जाए। नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से दिलीप कुमार साहू, कार्यवाहक अध्यक्ष सुंदरलाल साहू सहित शहर जिला साहू संघ के सदस्य उपस्थित रहे।

रामाराम जलाशय योजना के लिए 1.16 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा सुकमा जिले के विकासखण्ड सुकमा के अंतर्गत रामाराम जलाशय योजना के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 1 करोड़ 16 लाख 6 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। यह पहल सुकमा क्षेत्र में कृषि विकास को गति देने और स्थानीय किसानों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना के प्रस्तावित कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर क्षेत्र के स्थानीय किसानों को 69 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने लगेगी। जल संसाधन विभाग द्वारा इस योजना के कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराने के लिए मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग (जगदलपुर) को आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। योजना के पूर्ण होने के बाद, रूपांकित सिंचाई क्षमता में आ रही कमी पूरी होगी और पूरे क्षेत्र को पर्याप्त सिंचाई का लाभ मिलेगा।

नील हरित शैवाल से सुधर रही मिट्टी की सेहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसान अब जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में प्रदेश के कई किसान मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, उत्पादन लागत कम करने और दीर्घकालीन कृषि लाभ सुनिश्चित करने के लिए जैविक विकल्पों की ओर अग्रसर हैं। नील हरित शैवाल (ब्लू-ग्रीन एल्गी) का उपयोग भी ऐसी ही एक प्रभावी तकनीक के रूप में उभर रहा है, जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति कर उसकी उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। प्रदेश में कई प्रगतिशील किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक खेती को अपनाते हुए जैविक उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। सरगुजा जिले के किसान श्री धनेश्वर प्रसाद ने भी कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अपनी खेती में नील हरित शैवाल आधारित जैविक पद्धति को अपनाया है। मिट्टी परीक्षण में नाइट्रोजन की कमी पाए जाने के बाद उन्होंने अपने स्तर पर नील हरित शैवाल उत्पादन की पहल की, जिससे खेतों को प्राकृतिक पोषण उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

70- से 80 प्रतिशत राशि मिलेगी अनुदान के रूप में

पीएम ई-ड्राइव योजना-छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क की तैयारी, मांगी जमीन

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का नेटवर्क विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों और जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं से ऐसे उपयुक्त स्थलों की जानकारी मांगी है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जा सकें। यह पहल केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत की जा रही है। इस योजना के लिए 70 से 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का अनुमान है कि नगर निगम क्षेत्रों में दोपहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगभग 25 से 30 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए स्थानीय निकायों को संभावित स्थलों का चिन्हांकन कर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

खास खबर

क्यों बढ़ रही है चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत

देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रोत्साहन योजनाएं चला रही हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने के साथ सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता रही है। जानकारों का मानना है कि चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार हुए बिना इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाना मुश्किल होगा। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की है, जिसके तहत सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

चार्जिंग स्टेशन के लिए लगभग 800 वर्गफीट भूमि जरूरी

किन स्थानों को मिलेगी प्राथमिकता

विभागीय निर्देशों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाने हैं जहां वाहन खड़े करने की पर्याप्त क्षमता हो और आम लोगों की पहुंच आसान हो। पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, बाजार क्षेत्र, अस्पताल परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थानों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। साथ ही सरकारी या नगर निगम स्वामित्व वाली भूमि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। स्थल चयन के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि वहां बिजली कनेक्शन उपलब्ध हो या निकट भविष्य में आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। प्रत्येक प्रस्तावित स्थल का अक्षांश-देशांतर और कम से कम दो फोटोग्राफ भी भेजने होंगे।

चार्जिंग स्टेशन के लिए क्या होंगे मानक?

दस्तावेज के अनुसार प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन के लिए लगभग 800 वर्गफुट भूमि उपलब्ध होना आवश्यक होगा। इसके अलावा प्रत्येक स्टेशन की न्यूनतम कुल क्षमता 144 किलोवाट रखने का प्रस्ताव है, ताकि एक साथ कई वाहनों को चार्ज किया जा सके। स्थल चयन से पहले उसकी व्यवहार्यता(फिजिबीलिटी) और उपयोगिता का परीक्षण भी किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक निवेश का अधिकतम लाभ मिल सके।

केंद्र सरकार देगी भारी अनुदान

योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय सहायता है। विभागीय पत्र के अनुसार 'बी' श्रेणी के नगर निगम क्षेत्रों में स्थापित होने वाले चार्जिंग स्टेशनों के लिए विद्युत अधोसंरचना (अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर) की लागत का 80 प्रतिशत और चार्जिंग मशीनों एवं उपकरणों की लागत का 70 प्रतिशत तक अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। शेष राशि की व्यवस्था संबंधित नगर निगमों को करनी होगी। इसके लिए उन्हें जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर उपलब्ध वित्तीय स्रोतों से आवश्यक धन जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए क्या मायने

छत्तीसगढ़ में अभी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार शुरुआती विस्तार के दौर में है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा जैसे शहरों में ई-स्कूटर और ई-कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित होने से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में लोगों का भरोसा बढ़ सकता है। सरकार के इस कदम को राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देने, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। फिलहाल नगर निगमों और नगर पालिकाओं से उपयुक्त स्थलों की पहचान कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है, जिसके बाद योजना के क्रियान्वयन की अगली प्रक्रिया शुरू होगी।

खेत बचाओ अभियान किसान मारो अभियान साबित हो रहा : धनेंद्र

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे "खेत बचाओ अभियान" की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह अभियान वास्तव में खेत बचाने का नहीं, बल्कि किसानों को संकट में डालने और उनकी समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है।

एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खरीफ फसल का सीजन शुरू हो चुका है और किसान खेती-किसानी के कार्यों में जुट गए हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। प्रदेश भर में किसान सोसायटियों और खाद केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार अब किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने की सलाह दे रही है, जो पूरी तरह से अव्यावहारिक और किसान विरोधी है।

किसानों के बजाय व्यापारियों को खाद

धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की सहकारी समितियों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के बजाय बड़े पैमाने पर निजी व्यापारियों को खाद की आपूर्ति कर रही है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का दायित्व किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए नए-नए अभियान चला रही है।

खाद न मिलने से किसान निराश

श्री साहू ने कहा कि एक ओर सरकार ने खाद के दाम बढ़ा दिए हैं, दूसरी ओर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध भी नहीं करा पा रही है। किसानों को ना ही सोसाइटी में और ना हीं बाजार में खाद मिल रहा है। ऐसे समय में किसानों को उर्वरकों का उपयोग कम करने की सलाह देना उनकी समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि उन्हें बर्बाद करना है। इससे किसान वर्ग में भारी नाराजगी और निराशा का माहौल है। श्री साहू ने कहा है कि भाजपा सरकार बहानेबाजी छोड़कर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाए तथा उपलब्ध समस्त खाद को निजी व्यापारियों के बजाय सहकारी समितियों और सोसायटियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिससे खरीफ सीजन की खेती प्रभावित न हो और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

भाजपा बोली-जनता की लिक्विडिटी छीनकर गोवा के होटलों में निवेश कर रही थी कांग्रेस

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय ने शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश किए गए छठवें पूरक आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा, इसमें कांग्रेस सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के नए और चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इस महाघोटाले के कारण आज छत्तीसगढ़ में नकदी और मुद्रा तरलता (लिक्विडिटी) का भारी अभाव दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता का हक मारकर यहां का पैसा दूसरे राज्यों में अवैध रूप से निवेश किया गया, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी पीछे चली गई है।

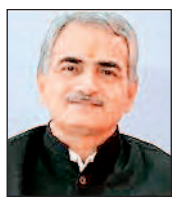

श्री पाण्डेय ने कहा, शराब घोटाले की काली कमाई का लगभग 110 करोड़ रुपया कथित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के माध्यम से नॉर्थ गोवा के 'होटल वेस्टिन' को खरीदने में लगाया गया है। ईडी ने इसके पुख्ता प्रमाण चार्जशीट में जोड़े हैं। इस पूरे घोटाले में अब तक लगभग 89 आरोपियों को नामजद किया गया है, और अपराधियों से कुल 1,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को ईडी द्वारा फ्रीज या सीज किया जा चुका है। ताजा चार्जशीट में ही 200 करोड़ रुपए की नई बेनामी और अवैध संपत्ति का पता चला है। श्री पाण्डेय ने मांग की है कि बेनामी ट्रांजेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इस भयावह खेल पर कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। श्री पाण्डेय ने कहा, छत्तीसगढ़ की यह लूट अकेले नहीं हुई। इसमें राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और बड़े व्यवसायियों की तिकड़ी का एक मजबूत सिंडिकेट सक्रिय था। इस सिंडिकेट के कई तत्कालीन मंत्री और अधिकारी आज भी जेलों में बंद हैं। श्री पाण्डेय ने सवाल उठाया, इतने बड़े घोटाले और गंभीर आरोपों के बाद भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। कांग्रेस के पास केंद्रीय एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाने के अलावा कोई सीधा स्पष्टीकरण नहीं है।

बोरियाखुर्द में आरसीसी नाली निर्माण का कार्य जल्द होगा शुरू

रायपुर विकास प्राधिकरण ने टेंडर जारी किया

■ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना में 1800 आवासों का किया था निर्माण

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

रायपुर विकास प्राधिकरण की बोरियाखुर्द स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना के रहवासियों की सालों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। सालों पुरानी जर्जर नाली की जगह नई निकास नाली का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है।

दरअसल, वर्ष 2009 में निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत करीबन 1800 आवासों का निर्माण कराया गया था। उस समय की बनाई गई ज्यादातर नालियां जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जल निकासी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय रहवासियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा बोरियाखुर्द में नालियों के पुनर्निर्माण की मांग लगातार उठाई जा रही थी।

अब प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी और रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू ने इसे संज्ञान में लिया है। रायपुर विकास प्राधिकरण अपने स्वयं के व्यय से नाली निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्राधिकरण ने निविदा जारी कर दी है।

पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे

नगरीय निकायों में 30 जून तक होंगे स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

मेहनतकश स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में बदलाव लाने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के छह साल पूरे होने के मौके पर नगरीय निकायों में 30 जून तक लोक कल्याण मेलों के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही जिला मुख्यालय वाले सभी नगरीय निकायों में जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सवों का भी आयोजन किया जाएगा।

राज्य शासन ने स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेलों के आयोजन के लिए सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से जारी परिपत्र में नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स), शहरी गरीबों एवं असंगठित श्रमिकों को वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लाभों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण ही नहीं, सुरक्षा और सम्मान भी : साव

होंगे स्वनिधि महोत्सव

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे, जबकि जिला मुख्यालयों में विशेष रूप से स्वनिधि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों में बैंकों के प्रतिनिधि छोटे व्यापारियों को ऋण स्वीकृति, वितरण, यूपीआई पंजीयन, क्यू-आर कोड सुविधा और डिजिटल भुगतान संबंधी सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराएंगे। स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक सम्मान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

साव ने कही ये बात

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से बैंकों को लंबित ऋण प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने और फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से नए आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति को समय पर पूंजी मिलती है, तो केवल उसका व्यवसाय ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसके बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा और जीवन की उम्मीद भी मजबूत होती है।

भ्रम फैलाकर आदिवासी समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस : कश्यप

कश्यप ने कहा- बैज का बयान कांग्रेस की आदिवासी-विरोधी राजनीति को छिपाने का प्रयास

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सरकार पर से आदिवासी समाज का भरोसा उठ गया है। भाजपा सरकार आदिवासी समाज को प्रताड़ित कर रही है। राज्य के आदिवासी, सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं।

■ भाजपा सरकार आदिवासियों के मौलिक और नैसर्गिक अधिकार से वंचित करने का षड़यंत्र : बैज

वन मंत्री केदार कश्यप ने श्री बैज के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस को आदिवासी हितों पर सवाल उठाने से पहले अपना राजनीतिक इतिहास देखना चाहिए। जिन कानूनों और अधिकारों की आज कांग्रेस बात कर रही है, उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा स्वयं कांग्रेस की नीयत और नीतियां रही हैं। वनमंत्री कश्यप ने कहा, कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक समझकर राजनीति की, लेकिन उन्हें उनके अधिकारों, संसाधनों और विकास से जोड़ने का ईमानदार प्रयास कभी नहीं किया। आज जब छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, वनाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आदिवासी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, तब कांग्रेस इसे भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है।

कांग्रेस का जनाधार आदिवासी क्षेत्र में सिकुड़ रहा

उन्होंने कहा कि दीपक बैज और कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद पेसा और वनाधिकार कानून का लाभ अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच सका। आदिवासी क्षेत्रों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आजीविका के अवसरों का अभाव किसकी देन था, यह देश अच्छी तरह जानता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का वास्तविक दर्द आदिवासी अधिकार नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में उसका लगातार सिकुड़ता जनाधार है।

भाजपा आदिवासियों को वनवासी बताकर उनके अधिकार छीनना चाह रही : बैज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, भाजपा के राज सुनियोजित तरीके से आदिवासियों पर उनकी संस्कृति पर हमले हो रहे। भाजपा सरकार जल, जंगल, जमीन पर से आदिवासियों के मौलिक और नैसर्गिक अधिकार से वंचित करने का षड़यंत्र कर रही है। पेसा कानून को कमजोर किया जा रहा है, केंद्र ने वन अधिकार अधिनियम 2006 में संशोधन कर दिया है। आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिशों का कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा,भाजपा आदिवासियों को वनवासी बताकर उनका मूल संस्कृति से उनको तोड़ने का काम कर रही है। आरएसएस और भाजपा आदिवासियों को उनके जंगल पर से प्राकृतिक अधिकार और पहचान छीनना चाहते है। आदिवासी समाज को वनवासी बताना भाजपा का षड़यंत्र है। आदिवासियों के उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जुड़े विषयों पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आदिवासी अस्मिता और सम्मान का मुद्दा है।

खबर संक्षेप

पीएससी सेंटर में रहेगी ओआरएस की व्यवस्था

रायपुर। सीजी पीएससी मेंस 6 से 9 जून तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसकी संपूर्ण तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह ने रेडक्रॉस सभाकक्ष में बैठक ली। कलेक्टर ने कहा, सभी केन्द्राध्यक्ष परीक्षार्थियों की सुविधा पर ध्यान दें। स केन्द्रों में मूलभूत सुविधा, बिजली, पेयजल इत्यादि सुनिश्चित करें। साथ ही गर्मी को देखते हुए, कूलर, ओआरएस और ठंडे पेयजल की भी व्यवस्था करें। सभी केन्द्राध्यक्ष परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का होना सुनिष्चित करें। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सीजीडीएफ का भी होगा विस्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन में आगामी संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत सितंबर माह के बाद वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी सहित सभी पदों पर परिवर्तन किए जाने की संभावना है। योग्य उम्मेदवारों का चयन छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन की प्रशासनिक बॉडी के द्वारा किया जाएगा। सीजीडीएफ के प्रदेश अध्यक्ष डा. हीरा सिंह लोधी ने बताया कि संगठन के प्रति समर्पित, सक्रिय और योग्य सदस्य इन पदों के लिए अपनी रुचि और दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में फेडरेशन का विस्तार किया जाएगा। इससेसंगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकेगा और डॉक्टरों की समस्याओं एवं हितों की आवाज़ को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

निजी फार्मेसी कॉलेजों में बिना परीक्षा प्रवेश का दावा अवैधः आईपीए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र-हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध इण्डियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रांच ने राज्य के कुछ निजी शिक्षण संस्थानों और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे अवैध प्रवेश विज्ञापनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने तकनीकी शिक्षा संचालनालय नया रायपुर में एक शिकायत दर्ज कराकर दोषी संस्थानों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव फार्मासिस्ट राहुल वर्मा ने बताया कि जगदलपुर और भिलाई के संस्थानों द्वारा बिना परीक्षा सीधे प्रवेश का भ्रम फैलाया जा रहा है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी निजी संस्थान के बहकावे में न आएं। फार्मेसी में प्रवेश केवल और केवल शासकीय काउंसलिंग और पीपीएचटी परीक्षा के माध्यम से ही लें, ताकि आपका भविष्य और समाज का स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहें।

रेलवे स्टेशन-बस टर्मिनल में लगी नशामुक्ति प्रदर्शनी

रायपुर। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर एक दिन के लिए नशामुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बस टर्मिनल भाठागांव में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन महापौर मीनल चौबे और रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने किया। साथ में ब्रह्माकुमारी भावना, ब्रह्माकुमारी चंद्रकला, ब्रह्माकुमारी निधि और ब्रह्माकुमारी पूर्णिमा दीदी उपस्थित थीं। इसी तरह रेलवे स्टेशन में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौड़, रेल मण्डल वाणिज्य प्रबंधक (डीसीएम) राकेश सिंह और रायपुर सेवाकेंद्र की संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने किया।

विश्व साइकिल दिवस पर बेमचा से परसवानी तक निकली रैली

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा ग्राम पंचायत बेमचा के संयुक्त तत्वावधान में 3 जून को ग्राम बेमचा में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। जिसमें स्थानीय युवाओं ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ अपनी सहभागिता दर्ज कराई। ग्राम बेमचा से परसवानी तक एक भव्य साइकिल दौड़ (रैली) का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला भाजपा कोषाध्यक्ष राहुल चंद्राकर, अध्यक्षता बेमचा सरपंच गुमान यादव, विशिष्ट अतिथि डॉ. सेवन दास मानिकपुरी एवं माय भारत से अशोक चक्रधारी उपस्थित रहे। राहुल चंद्राकर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि साइकिल चलाना न केवल हमारी शारीरिक सेहत को मजबूत करता है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक बड़ा योगदान है। गुमान यादव ने युवाओं और ग्रामीणों को अपने दैनिक जीवन में साइकिल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। डॉ. सेवनदास मानिकपुरी ने खेल और शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साइकिल चलाने के वैज्ञानिक फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अशोक चक्रधारी ने युवाओं को साइकिल चलाने और फिटनेस के प्रति विशेष रूप से जागरूक करते हुए बताया कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने तथा खुद को निरोगी बनाने के लिए साइकिल सबसे बेहतरीन माध्यम है। साथ ही उन्होंने युवाओं को माई भारत मंच के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए राष्ट्र निर्माण से जुड़ने की बात कही। मेरा युवा भारत की ओर से सहभागी युवाओं को विशेष टी-शर्ट प्रदान की गई। इस अवसर पर पंकज चंद्राकर, पुष्कर साहू, लक्ष्मी चंद्राकर, ओम प्रकाश, जुगेश नाथ भोई आदि मौजूद रहे।

चर्चा : बैठक में संगठन के विस्तार, अनेक विषयों पर हुई व्यापक चर्चा

संकुल शैक्षिक समन्वयक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष बने लखन

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

छत्तीसगढ़ संकुल शैक्षिक समन्वयक शिक्षक संघ की प्रांतीय वर्चुअल बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, समन्वयकों की समस्याओं तथा शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से लखन कुर्रे को संघ का कार्यकारी प्रांताध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांताध्यक्ष पूर्णानंद मिश्रा ने कहा कि संकुल शैक्षिक समन्वयक शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके अधिकारों, सम्मान और कार्यगत समस्याओं के समाधान के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत रहेगा। कार्यकारी अध्यक्ष रामचंद्र सोनवंशी ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने तथा समन्वयकों की वास्तविक समस्याओं को शासन एवं विभाग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष ओमप्रकाश बघेल ने संगठनात्मक एकता और समन्वयकों के हितों की रक्षा के लिए सभी पदाधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में बस्तर संभाग से नितेश उपाध्याय (जिलाध्यक्ष कांकेर) एवं प्रेम प्रकाश चापड़ी (जिलाध्यक्ष बीजापुर) ने कहा कि समन्वयकों को शिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए पर्याप्त अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दुर्ग संभाग प्रभारी कमलेश साहू (बेमेतरा) तथा मुरली झरिया (जिलाध्यक्ष कबीरधाम) ने समन्वयकों पर बढ़ते गैर-शैक्षणिक कार्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें सीमित करने की मांग की। रायपुर संभाग अध्यक्ष आशीष साहू ने कहा कि समन्वयकों की भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। ताकि, विभाग एवं समाज में उनके प्रति गलत धारणाओं का निराकरण हो सके।

बिलासपुर संभाग से नेमीचंद भास्कर (जिलाध्यक्ष मुंगेली) तथा विकास रंजन सिन्हा (जिलाध्यक्ष रायगढ़) ने अर्जित अवकाश की प्रविष्टि सभी समन्वयकों की सेवा पुस्तिका में सुनिश्चित कराने की मांग रखी। सरगुजा संभाग से अशोक गुप्ता (जिलाध्यक्ष कोरिया), राजकुमार सिंह (जिलाध्यक्ष सूरजपुर) एवं सत्यम सिंह नायक (जिलाध्यक्ष जशपुर) ने समन्वयकों की कार्यप्रणाली एवं अन्य राज्यों में संचालित व्यवस्थाओं का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में बेहतर मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। बैठक मां बस्तर जिलाध्यक्ष शरद श्रीवास्तव, सुकमा जिलाध्यक्ष फिरोज खान, कोंडागांव जिलाध्यक्ष शुभाऊ नेताम, दुर्ग जिलाध्यक्ष ललित बिजौर, बालोद जिलाध्यक्ष पारख देवांगन, मोहला-मानपुर जिलाध्यक्ष आरके नंदे, रायपुर जिलाध्यक्ष हरीश दीवान, धमतरी जिलाध्यक्ष लोकेश पांडेय, महासमुंद जिलाध्यक्ष अनिल ढीढी, गरियाबंद जिलाध्यक्ष विनोद सिन्हा, जांजगीर-चांपा जिलाध्यक्ष निधिलता जायसवाल, सारंगढ़ जिलाध्यक्ष भागवत साहू, सक्ती जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौर, सरगुजा जिलाध्यक्ष उमेश मिश्रा तथा एमसीबी जिलाध्यक्ष गणेश यादव की उपस्थिति रही।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन शिक्षामंत्री के आतिथ्य में कराने का प्रयास, समन्वयकों की समस्याओं से विभाग को अवगत कराना, संगठन का पुनर्गठन एवं नई नियुक्तियां, अन्य राज्यों में समन्वयकों को दिए जा रहे दायित्वों का अध्ययन, सभी समन्वयकों के अर्जित अवकाश को सेवा पुस्तिका में दर्ज कराने की पहल, समन्वयकों के विरुद्ध बनाए जा रहे नकारात्मक नैरेटिव को दूर करने के प्रयास तथा समन्वयकों से गैर-शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर रोक लगाने की मांग प्रमुख रूप से शामिल हैं। बैठक के अंत में नवनियुक्त कार्यकारी प्रांताध्यक्ष लखन कुर्रे ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन समन्वयकों के सम्मान, अधिकार और शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगा।

शिक्षक फेडरेशन ने की टेट परीक्षा कराने की मांग

महासमुंद। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी शिक्षकों को करना होगा। टीईटी (टेट) परीक्षा उत्तीर्ण पश्चात फिर से टेट का मुद्दा गरम हो गया है। हालांकि टेट और शिक्षकों के परीक्षा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने 31 अगस्त 2027 तक टेट उत्तीर्ण की अनिवार्यता में एक वर्ष का अतिरिक्त राहत प्रदान करते हुए 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। इस मुद्दे पर शिक्षकों की स्थिति से अवगत कराने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला महासमुंद द्वारा ईश्वर चंद्राकर के नेतृत्व और सिराज बक्श कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य गौरव साहू प्रदेश महासचिव, दिनेश नायक प्रांतीय पदाधिकारी अनुशासन समिति, प्रकाश बघेल ब्लॉक अध्यक्ष बागबाहरा, आत्माराम साहू ब्लॉक कोषाध्यक्ष सहित सदस्यों की उपस्थिति में भाजपा जिला अध्यक्ष ऐतराम साहू से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। इस मुलाकात और चर्चा में जिला अध्यक्ष ईश्वर चंद्राकर ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को केंद्रित करते हुए शिक्षकों की मंशा से अवगत कराया गया। टेट परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विभागीय परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाएगा और शिक्षकों के इतने वर्ष के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ष के शिक्षकों के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक में रियायत देकर वर्ष में 2 बार परीक्षा का आयोजन नियमित रूप से करेगा तो हमारे शिक्षक न्यायालय द्वारा दिए गए तिथि तक उत्तीर्ण कर लेगे। टेट परीक्षा के विषय पर आदित्य गौरव साहू, प्रकाश बघेल, दिनेश नायक ने भी अपनी बात रखी, जिस पर ऐतराम साहू ने पूर्ण आश्वासन दिया कि शिक्षकों के लिए शीघ्र विभागीय परीक्षा के आयोजन पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से शीघ्र पत्र सौंपाकर चर्चा करूंगा। जल्द ही राज्य के शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन करने का पहल होगा। जिससे शिक्षक राहत महसूस करेंगे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने सभी शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि अनावश्यक तनाव ना लें। शासन की ओर सभी स्तर पर फेडरेशन की बात हो रही है ओर बीच का रास्ता निकालने पर जोर दिया जा रहा है। मुलाकात के दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा के साथ थानसिंह दीवान सहित फेडरेशन से प्रमुख रूप से दुर्वासा गोस्वामी, दामोदर यादव, ठाकुर प्रसाद साहू, शैलेंद्र सिन्हा, श्याम पटेल, संदीप साहू सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे।

प्रो.शाहिद अली की पुनः नियुक्ति को लेकर जारी है विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, लेकिन विवि ने दे दी एंट्री! भड़के छात्रों का बवाल

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

पत्रकारिता विवि में मंगलवार दोपहर जमकर हंगामा हुआ। यहां एबीवीपी ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन, कुलपति कार्यालय का घेराव किया। एबीवीपी ने विवि में प्रशासनिक अनियमितताओं, छात्र विरोधी नीतियों एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अभाविप ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सेवा समाप्ति की कार्यवाही के बावजूद पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली को बिना किसी वैधानिक आदेश के पुनः विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया है। साथ ही वर्ष 2019 में डॉ. शैलेंद्र खंडेलवाल की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठाते हुए इसकी जांच की मांग की गई। परिसर में लगभग 7 करोड़ की लागत से निर्मित नए ऑडिटोरियम की हालत जर-जर हो चुकी है। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त करते हुए एबीवीपी ने इसकी भी तकनीकी जांच की मांग की है।

- मामला पत्रकारिता विवि का, मंगलवार दोपहर रही गहमागहमी की स्थिति

बदले जा रहे पाठ्यक्रम के नाम

प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम के नाम परिवर्तित किए जाने से उत्पन्न भ्रम, परीक्षा अवधि में लगातार विद्युत बाधित होने, छात्रावास में दूषित पेयजल, मेस की निम्न गुणवत्ता, खेल सुविधाओं के अभाव, बस परिवहन की अव्यवस्था एवं विद्यार्थियों के लिए स्टूडियो सुविधाओं के उपयोग न होने जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री अनंत सोनी ने कहा, सेवा समाप्ति के आदेश के बाद भी किसी व्यक्ति को विवि में कार्य करने की अनुमति प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

इंडक्शन इस्तेमाल की अनुमति

छात्रावासों में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, निर्धारित स्थान पर इंडक्शन उपयोग की अनुमति तथा करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित स्टूडियो को विद्यार्थियों के लिए तत्काल संचालित करने की मांग भी की गई। अभाविप के महानगर मंत्री सुजल गुप्ता ने कहा, करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित ऑडिटोरियम उद्घाटन से पूर्व ही क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पहुंच गया है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। घंटों चले प्रदर्शन एवं घेराव के पश्चात कुलसचिव ने विद्यार्थियों से जुड़ी अन्य समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद ही छात्रों का विरोध-प्रदर्शन समाप्त हुआ। सुमय, हर्षित कौर, मन साहू, संकल्प राजकमल, रिद्धिमा वर्मा सहित अन्य छात्र प्रदर्शन में शामिल रहे।

संत माता कर्मा ब्लाक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी की बैठक में निर्णय

पांच को प्रदर्शन, सात वार्डों के कांग्रेसी कार्यकर्ता करेंगे घेराव

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

देवपुरी गुरुद्वारा में 5 जून को जोन 10 कमिश्नरी के सात वार्डों के लिए लगाए जा रहे सुशासन तिहार का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस दिन घेराव कर सुशासन तिहार के विरोध में प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं आने, महतारी वंदन के नाम से केवाइसी में लोगों को हो रही परेशानी और बुजुर्गों को पिछले 1 साल से लंबित मासिक पेंशन को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन के नेतृत्व, पंकज शर्मा के मार्गदर्शन और संत माता कर्मा ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हीरेंद्र देवांगन की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

- देवपुरी में सुशासन तिहार का विरोध
- पीएम आवास हितग्राहियों के खाते में पैसा नहीं आ रहा, महतारी वंदन के केवाईसी में दिक्कत

रायपुर नगर निगम द्वारा जोनवार लगाए जा रहे सुशासन तिहार की कड़ी में 5 जून को जोन 10 क्षेत्र स्थित देवपुरी गुरुद्वारा में सुशासन तिहार शिविर आयोजित है। शिविर में 7 वार्ड के रहवासी शासन की विभिन्न योजनाओं और जन समस्या को लेकर आवेदन करेंगे। शिविर लगने से पहले इसका विरोध होना शुरू हो गया है। मंगलवार को संत माता कर्मा ब्लाक कांग्रेस कमेटी की मंडल कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 5 जून को भाजपा शासन के सुशासन तिहार जोन 10 का देवपुरी गुरुद्वारे में आयोजन को लेकर घेराव करने रणनीति बनाई गई। कांग्रेसी नेता पंकज शर्मा और हीरेंद्र देवांगन ब्लाक अध्यक्ष, हरदीप कौर, मोहन साहू, यवनेश जोशी, सहदेव व्यवहार, तुलाराम साहू सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने यह बात रखी कि पहले भी सुशासन तिहार लगाया गया उसमें आज तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, अब दोबारा सुशासन तिहार का औचित्य क्या है? बैठक में जोन के सभी वार्डों में नियमित सफाई नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी पर चिंता जताई गई।

गर्मी में टमाटर की लोकल फसल को मिल रहा अच्छा भाव

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

गर्मी वाले टमाटर की लोकल फसल भी अंतिम चरण पर है। सिहावा और नगरी में कई किसान गर्मी में फसल ले रहे हैं। इनको भी अच्छा भाव मिल रहा है। अब इनकी फसल भी ज्यादा समय के लिए नहीं बची है। इसके बाद बाहर के टमाटर के भरोसे ही पूरा प्रदेश चलेगा। इस समय थोक में टमाटर के दाम 30 रुपए और चिल्हर में 40 रुपए हैं। इधर चिल्हर में दूसरी सब्जियों में भी भारी लूट है। थोक से चिल्हर में दाम डेढ़ से दो गुना ज्यादा हैं। टमाटर का अपने राज्य में भारी उत्पादन होता है। इसकी फसल दीपावली से प्रारंभ होकर अप्रैल तक आती है। ऐसे में इसके दाम आमतौर पर दिसंबर से कम होकर थोक में 2 से 3 रुपए और चिल्हर में 5 से 7 रुपए हो जाते हैं। अब तो अप्रैल से लगातार बाहर के टमाटरों के साथ सिहावा और नगरी के लोकल टमाटर भी गर्मी में आ रहे हैं। इसकी ज्यादातर खपत धमतरी और आस-पास में ज्यादा होती है। एक-दो ट्रक माल रायपुर भी आता है। इस समय लोकल फसल को 600 से 700 रुपए का दाम प्रति क्रेट मिल रहा है। बाहर का टमाटर इससे करीब सौ रुपए ज्यादा है। इसके दाम 800 रुपए क्रेट हैं।

- चिल्हर में सब्जियों में भी बड़ी लूट, थोक से दाम डेढ़ से दो गुना ज्यादा

सब्जियों में ऐसी लूट : सब्जियों के दाम में थोक और चिल्हर में जमीन आसमान का अंतर है। पता गोभी थोक में 10-12 रुपए किलो है। इसके चिल्हर में दाम 30 रुपए किलो हैं। फूल गोभी थोक में 15 से 20 चिल्हर में 30 से 40 रुपए, भिंडी थोक में 20 से 25, चिल्हर में 40 से 50 रुपए किलो, खीरा थोक में 10 से 12 रुपए चिल्हर में 30 रुपए किलो, लौकी थोक में 12 से 15 रुपए चिल्हर में 30 रुपए किलो रुपए किलो बिक रहा है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग

रायपुर। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे एवं भाजपा नेत्री और रायपुर जिला पंचायत सभापति सरोज चंद्रवंशी भी शामिल थीं। धरसीवा थाना अंतर्गत सिलियारी चौकी क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस अधीक्षक श्वेता सिंह को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि घटना 18 अप्रैल की बताई जा रही है, किंतु मामले में समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। इस दौरान मांग की गई कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषी आरोपी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सिलियारी चौकी प्रभारी जितेंद्र दुबे की भूमिका की जांच कर उन्हें तत्काल निलंबित किए जाने की मांग भी की गई।

खबर संक्षेप

साइकिल चलाना शरीर के लिए फायदेमंद

महासमुंद। विश्व साइकिल दिवस पर संवेदना समूह खरोरा के सदस्य मुकेश चंद्राकर ने कहा कि साइकिल चलाने से सेहत ठीक रहती है। आमतौर बच्चे ने 6 से 11 साल की उम्र के बीच साइकिल चलाना सीखते हैं। हालांकि, हर बच्चे का विकास अलग होता है। इसलिए वे अलग-अलग उम्र में साइकिल चलाने के लिए तैयार होते हैं।

10 दिवस के भीतर मुक्तिधाम निर्माण कार्य को मिली स्वीकृति

महासमुंद। सुशासन तिहार के दौरान आमजन की समस्याओं एवं मांगों के त्वरित निराकरण करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जनपद पंचायत बागबाहरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरौद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई घोषणा को मात्र 10 दिवस के भीतर पूरा कर दिया है। विगत 22 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरौद पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में मुक्तिधाम निर्माण की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री साय ने तत्काल मुक्तिधाम निर्माण कार्य की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर विनय लंगेह ने तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत नंदनवार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मुक्तिधाम निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के मात्र 10 दिवस के भीतर स्वीकृति जारी हो गई।

नयापारा में एनपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता 10 से

बिरकोनी। ग्राम नयापारा में एनपीएल सीजन वन क्रिकेट टीम के युवाओं द्वारा 10 जून को मौहारी मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। खेल प्रातः10 बजे से शाम 5 बजे तक एक सप्ताह खेला जाएगा। जिसमें 31 टीम के खिलाड़ी पहले आओ पहले पाओ के तहत भाग लेंगे। प्रत्येक मैच 6 ओवर का होगा। स्पर्धा में पुरस्कार प्रथम तीस हजार, द्वितीय पंद्रह हजार, तृतीय सात हजार रुपए रखा गया है। प्रवेश शुल्क 2000 रुपए निर्धारित है। प्रतियोगिता का स्तर केवल ग्रामीण टीमों को प्रथमिकता देगी। 35 किलोमीटर दूर से आने वाले टीमों को विशेष छूट दी जाएगी। एक दिन में एक टीम का क्वालीफाई राउंड होगा। इस टूर्नामैच में आयोजक समिति द्वारा कोई मैच नहीं खेला जाएगा। अध्यक्ष प्यारे लाल पुरैना, उपाध्यक्ष आशीष जांगड़े, अमितेश निषाद, दिनेश पाटिल सहित खिलाड़ी प्रतियोगिता को सफल बनाने में जुटे हुए है।

पहल : पारदर्शी एवं जवाबदेही शासन के लिए व नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित होगा : कलेक्टर

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

राज्य में आम जनता को अपनी शिकायत

- सीएम हेल्पलाइन 1076 के प्रभावी संचालन के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल के अधिकारियों ने दी जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण

दर्ज कराने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा उनके शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने के लिए शीघ्र ही सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरूआत होने वाली है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सीएम हेल्पलाईन के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों विशेष प्राथमिकता के साथ निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में उक्ताशय के निर्देश दिए हैं।

इस मौके पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल के प्रमुख आरके शर्मा एवं आईटी मैनेजर सौरभ कांत एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण के संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर विनय लंगेह ने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत को आम जनता के शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत, सुलभ और विश्वसनीय माध्यम प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य

शासन द्वारा शुरू किए जा रहे अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का गुणवत्तायुक्त ढंग से त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी मयंक पांडेय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

इस मौके पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल के प्रमुख आरके शर्मा ने सीएम हेल्पलाईन के अंतर्गत शिकायत प्रबंधन प्रणाली के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ऑनलाईन शिकायतों का पंजीयन, विभिन्न स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग के साथ-साथ चरणबद्ध प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन का उद्देश्य आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं और सेवाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाना है। साथ ही सीएम पोर्टल के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का निर्धारित समयावधि में लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का गुणवत्तायुक्त ढंग से निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि सीएम हेल्पलाईन सेंटर सप्ताह के सातों दिन एवं 24 घंटे संचालित रहेगा। इसके माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 एवं 18002333300 के अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसे आधुनिक माध्यमों में से किसी भी एक माध्यम से किसी भी समय आसानी से अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज होने के साथ ही मिलेगी एक विशिष्ट पहचान संख्या

उन्होंने कहा कि सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज होने के साथ ही उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता को उनके शिकायत से संबंधित विभाग, अधिकारी के पास लंबित होने की जानकारी तथा कार्यवाही की प्रक्रिया के अलावा समाधान में लगने वाले समय आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी पूरी तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ी होगी, जिसमें हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और शिकायतों के अनावश्यक लंबित रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान शर्मा ने कहा कि इसमें नागरिकों के फीडबैक की भी सुविधा होगी। साथ ही आवेदकों के समस्याओं के समाधान होने के बाद संबंधित आवेदक से सीधे संपर्क कर उसकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत यदि आवेदक समाधान से पूरी तरह से संतुष्ट होता है, तभी शिकायत का पूर्ण निराकरण माना जाएगा। लेकिन यदि कोई असंतुष्ट है तो शिकायत स्वतः सक्रिय हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग की इस व्यवस्था से प्रशासन अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्रिय बनेगा। जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का तेजी से निराकरण सुनिश्चित हो सकेगा।

जिला साहू संघ का वृहद पौधरोपण अभियान 7 को

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य

- पौध उपलब्ध कराने डीएफओ को सौंपा गया आवेदन

के निर्माण के उद्देश्य से प्रदेश साहू संघ के आह्वान पर जिला साहू संघ द्वारा आगामी 7 जून को जिले के समस्त तहसील परिक्षेत्रों एवं ग्राम स्तर पर वृहद पौधरोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। जिला साहू संघ के जिलाध्यक्ष ढालू राम

साहू ने बताया कि पौधरोपण कार्यक्रम को सफल बनाने तथा पर्याप्त संख्या में पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला साहू संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला वनमंडलाधिकारी से मुलाकात कर पौधे उपलब्ध कराने हेतु आवेदन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने वन विभाग से पर्यावरण संरक्षण के इस सामाजिक अभियान में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ढालू राम साहू के साथ झनक राम साहू, नंद कुमार साहू, मनोहर साहू, दिग्विजय साहू, राजेंद्र साहू एवं मानिक साहू उपस्थित रहे।

खेत बचाओ अभियान के तहत कृषकों को योजनाओं एवं तकनीकों की दी जानकारी

महासमुंद। खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा जिले के विभिन्न गांवो में कृषक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन जारी है। इसी क्रम में बसना एवं सरायपाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत नौगड़ी, जोगनीपाली, बालसी, भोथलडीह, सिरबोड़ा, चकरदा, बिरकोल, परसदा, कोटेनदरहा सहित अन्य ग्रामों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को टिकाऊ एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि योजनाओं एवं तकनीकों की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान किसानों को हरी खाद के उपयोग, खेत बचाओ अभियान के तहत रासायनिक उर्वरकों के कम एवं संतुलित उपयोग, तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता, लाभ एवं आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। कृषकों को धान उत्पादन में जैविक विकल्पों को अपनाने हेतु बीजीए (ब्लू ग्रीन एल्गी) यूनिट स्थापना के लाभ एवं प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसके अलावा पात्र कृषकों को एग्रीस्टैक पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया गया तथा पंजीयन से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विभागीय योजनाओं, अनुदान कार्यक्रमों एवं कृषि विकास से संबंधित विभिन्न सुविधाओं की भी जानकारी प्रदान की गई।

आधार पंजीयन एवं अपडेट शिविर का हुआ आयोजन

हरिभूमि न्यूज ⏭ सरायपाली

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार पंजीयन एवं आधार अपडेट शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में तहसील अंतर्गत ग्राम चट्टीगिरोला के आंगनबाड़ी केंद्र में आधार शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में उन बच्चों का आधार पंजीयन किया गया, जिनके दस्तावेज यूआईडीएआई के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सही पाए गए। साथ ही ऐसे हितग्राहियों के आधार कार्ड में आवश्यक सुधार एवं अपडेट की प्रक्रिया भी संपन्न की गई, जिनके आधार में त्रुटियां थीं अथवा बायोमेट्रिक सत्यापन संबंधी समस्याएं थीं। यूआईडीएआई की गाइडलाइन के अनुसार वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले हितग्राहियों के आधार विवरण सफलतापूर्वक अपडेट किए गए। शिविर में कुल 25 हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। इनमें तीन ऐसे हितग्राही भी शामिल थे, जिनके आधार कार्ड डीएक्टिव हो चुके थे, जिन्हें आवश्यक प्रक्रिया के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त शिविर सरायपाली क्षेत्र के निकट आयोजित होने के कारण बड़ी संख्या में हितग्राही अपने आधार संबंधी कार्यों के लिए शिविर स्थल पहुंचे। साथ ही आधार गाइड के जन्मदिवस के अवसर पर शिविर में उपस्थित बच्चों के लिए मिष्ठान वितरण की व्यवस्था की गई तथा बच्चों के साथ जन्मदिन मनाकर उन्हें विशेष खुशी प्रदान की गई।

बेलमुंडी सहकारी समिति से 108 किसानों को किया गया खाद वितरण, मिली राहत

हरिभूमि न्यूज ⏭ सरायपाली

खरीफ सीजन को देखते हुए प्रशासन द्वारा सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को यूरिया, डीएपी सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा प्रतिदिन खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण और वितरण की समीक्षा भी की जा रही है। जिला विपणन अधिकारी के अनुसार जिले की 159 सहकारी समितियों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा किसानों की मांग के अनुरूप लगातार वितरण किया जा रहा है। खरीफ वर्ष के लिए जिले को 60 हजार 850 टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके विरुद्ध अब तक 16 हजार 294 टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 26.78 प्रतिशत है।

वहीं किसानों को अब तक 7 हजार 720 टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। भंडारित उर्वरकों में 11 हजार 338 टन यूरिया, 1 हजार 928 टन डीएपी, 449 टन एनपीके तथा 1 हजार 496 टन एसएसपी शामिल हैं।

जिले की विभिन्न सहकारी समितियों में किसानों द्वारा किए जा रहे उठाव के तहत तोरेसिंहा सहकारी समिति बेलमुंडी के अंतर्गत अब तक 108 किसानों को खाद का वितरण किया गया है। गांव के किसान कमलेश ने बताया कि उन्हें आसानी से 8 बोरी यूरिया और 3 बोरी डीएपी प्राप्त हुआ। वहीं किसानों शरद और गुलाल ने भी बताया कि उन्हें बिना किसी परेशानी के डीएपी और यूरिया उपलब्ध हो गया है। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग उर्वरक कंपनियों से अतिरिक्त रैक प्राप्त कर लगातार भंडारण बढ़ा रहा है, ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रशासन द्वारा खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही समितियों और निजी विक्रेताओं के यहां नियमित निरीक्षण भी कराया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाए तथा मांग और आपूर्ति की दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।